हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

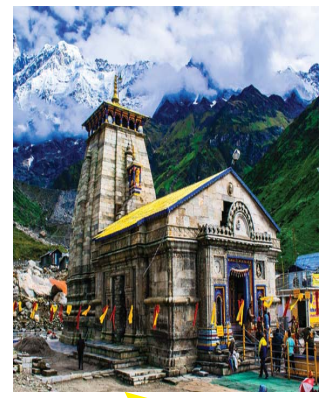

वर्ष:4 अंक:271 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये | pathpravah.com | हरिद्वार, रविवार, 05 अक्टूबर 2025

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया सम्मानः उत्तराखंड आपदा में बेहतर काम

पथ प्रवाह, संवाददाता - देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पटेलनगर स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह' में आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और आईटीबीपी के कर्मियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह सम्मान उन वीर कर्मियों के प्रति राज्य की कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आपदा के समय राहत एवं बचाव अभियानों में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता की भूमि ही नहीं, बल्कि भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण प्रदेश भी है, जहाँ भूस्खलन, अतिवृष्टि, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ आम हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि देवभूमि की यह धरती जितनी सुंदर है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। उन्होंने कहा कि 2013 की केदारनाथ आपदा, 2021 की ऋषिगंगा-धौलीगंगा त्रासदी और 2023 में जोशीमठ धंसाव जैसी घटनाओं ने प्रदेश को गहराई से झकझोरा है। इस वर्ष भी उत्तरकाशी, चमोली और देहरादून के कई इलाकों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने कठिन परिस्थितियाँ पैदा कीं। इन विकट स्थितियों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन के कर्मियों ने ग्राउंड जीरो पर दिन-रात डटे रहकर अनेक जिंदगियाँ बचाईं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि आपदा के समय इन राहतकर्मियों ने न केवल प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया, बल्कि राहत शिविरों का संचालन और पुनर्वास कार्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि सिल्क्यारा टनल में फँसे मजदूरों के बचाव अभियान को पूरा देश याद रखेगा। उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और बाबा बोखनाग के आशीर्वाद से यह मिशन सफल हो सका। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि जब भी वह आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं, तो राहत कर्मियों का जज्बा देखकर उन्हें विश्वास होता है कि उत्तराखंड किसी भी संकट से निपटने की क्षमता रखता है। उन्होंने आपदा प्रबंधन कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं देहरादून आकर आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द बाँटा और 1200 करोड़ रुपये की विशेष राहत राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि आपदा केवल सड़कों और इमारतों को ही नहीं तोड़ती, बल्कि लोगों के आत्मविश्वास और भविष्य को भी प्रभावित करती है। इसलिए राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आपदा पीड़ितों को केवल मुआवजा ही नहीं, बल्कि पुनर्वास और आजीविका के अवसर भी प्रदान किए जाएँ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एसडीआरएफ को ड्रोन, सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग और अत्याधुनिक रेस्क्यू गियर से लैस किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आगे कहा कि आपदा मित्र योजना के तहत गाँव-गाँव में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे आपदा की स्थिति में प्रथम उत्तरदाता बन सकें। साथ ही, सड़कों और पुलों के निर्माण में डिजास्टर रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी का उपयोग अनिवार्य किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण को स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, ताकि आने वाली पीढ़ी आपदा के खतरों से बेहतर ढंग से निपटना सीख सके।

समारोह में उपस्थित छात्रों ने नकल विरोधी कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

इस अवसर पर विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, स्वामी रूपेन्द्र प्रकाश, महंत कृष्ण गिरी महाराज, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरूगेशन और कार्यक्रम की संयोजक हनी पाठक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

भारत ज्ञान, कौशल का देश है, बौद्धिक क्षमता हमारी सबसे बड़ी शक्ति : मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को ज्ञान और कौशल का देश बताते हुए शुक्रवार को कहा कि भारतीयों की बौद्धिक क्षमता देश की सबसे बड़ी शक्ति है।

श्री मोदी ने यहां कौशल दीक्षांत समारोह में युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपये की पहलों का शुभारंभ किया, जिनमें पीएम सेतु योजना और नवोदय तथा एकलव्य मॉडल विद्यालयों में कौशल प्रयोगशाला योजना शामिल है। कौशल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों विद्यार्थी और कौशल प्रशिक्षु जुड़े। कार्यक्रम बिहार केन्द्रित था।

प्रधानमंत्री ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी की उपस्थिति में देश भर में आईटीआई (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट) की विभिन्न विधाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मान-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, राजीव रंजन सिंह, सुकांत मजूमदार और अन्य गणमान्य व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े थे।

मोदी सरकार ने कौशल विकास की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के साथ आईटीआई छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर दीक्षांत समारोह आयोजित करने की शुरुआत की है। श्री मोदी ने आज के दिन को एक यादगार बताया और कहा कि यह समारोह भारत द्वारा कौशल विकास को दी जाने वाली प्राथमिकता का प्रतीक है।

श्री मोदी ने कहा कि आज घोषित 60,000 करोड़ रुपये की पीएम सेतु योजना के तहत, आईटीआई अब उद्योगों के साथ और अधिक मजबूती से एकीकृत होंगे। नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1,200 कौशल प्रयोगशालाओं के शुरू होने से युवा भविष्य के कार्यों के लिए तैयार होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा, ÷ जैसे-जैसे कौशल बढ़ता है, राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है, निर्यात बढ़ता है और रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। ÷

उन्होंने याद दिलाया कि 2014 से पहले, भारत को 'नाजुक पांच' अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, जहां विकास दर कम थी और रोज़गार सृजन सीमित था। आज, भारत विनिर्माण और रोज़गार में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ शीर्ष तीन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर अग्रसर है।

श्री मोदी ने मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस उछाल से बड़े उद्योगों और एमएसएमई में उल्लेखनीय रोज़गार सृजन हुआ है, जिससे आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं सहित सभी को काफ़ी लाभ हुआ है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने में मदद की है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की, जिससे लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मोदी ने कहा कि पहले आज के इस कार्यक्रम को दीक्षांत समारोह के रूप में आयोजित किया जाना था, पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर को एक विशाल उत्सव बनाने का प्रस्ताव रखा और यह यह एक भव्य समारोह में बदल गया। प्रधानमंत्री ने इसी मंच से बिहार के युवाओं के लिए कई योजनायें और परियोजनायें समर्पित कीं, जिनमें वहां एक नये कौशल प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना, अन्य विश्वविद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार, एक नये युवा आयोग का गठन और हज़ारों युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि ये पहल बिहार के युवाओं के उज्जवल भविष्य की गारंटी हैं। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में युवा सशक्तिकरण के लिए आज का यह विशाल कार्यक्रम राज्य के युवाओं और महिलाओं के प्रति उनकी सरकार की प्राथमिकता को और भी दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ÷ भारत ज्ञान और कौशल का देश है, और यह बौद्धिक शक्ति इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कौशल और ज्ञान राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ जुड़ते हैं और उन्हें पूरा करने में योगदान देते हैं, तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में देश की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय प्रतिभा, स्थानीय संसाधनों, स्थानीय कौशल और स्थानीय ज्ञान को तेज़ी से आगे बढ़ाने की जरूरत है।

31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ होगा नक्सलमुक्त : शाह

जगदलपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नक्सलवाद को समाप्त करने की समय-सीमा दोहराते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर नक्सल मुक्त हो और विकास की लड़ाई में पीछे रह गए इलाके अब आगे बढ़ें।

श्री शाह ने आज मुरिया दरबार में आदिवासी ग्रामीण प्रतिनिधियों से संवाद कर और लालबाग में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बड़े विकास व्यापारिक वादे भी किए और नक्सलवाद को समाप्त करने की समय-सीमा दोहराई। उन्होंने मुरिया दरबार में आदिवासी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और वहीं से स्वदेशी मेला की ओर रवाना हुए।

इससे पहले अपने संबोधन में श्री शाह ने विकास कदमों को नक्सलवाद के जनाधार को तोड़ने वाली योजनाओं का हिस्सा बताया और ग्रामीण समुदायों को नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने का आग्रह किया। सभा में उन्होंने बार-बार इस नारे को दोहराया कि हम हर एक गांव को नक्सल-मुक्त करेंगे। साथ ही उन्होंने 31 मार्च 2026 की समय-सीमा पर सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहरायी।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद विकास की लड़ाई के कारण उपजा मुद्दा है और विकास पहुँचाकर ही अंत किया जा सकता है। बिजली, पेयजल, सड़कें, हर घर शौचालय, स्वास्थ्य बीमा और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे उपायों का जिक्र किया गया।

श्री शाह ने ग्रामीणों से अपील की कि जो लोग नक्सल विचारधारा से जुड़े हैं उन्हें समझाकर मुख्यधारा में लौटाने की कोशिश तथा शांति व पुनर्वास के रास्तों को अपनाने का अनुरोध किया। उनके भाषण और कार्यक्रमों का स्वर विकास-केंद्रित और सुरक्षा-एवं कल्याण मिश्रित रहा, जिसका उद्देश्य स्थानीय आदिवासी समाज के साथ सांस्कृतिक मेलजोल बनाए रखना और साथ ही सुरक्षा चुनौतियों का हल निकालना बताया गया

श्री शाह ने ग्राम-स्तर पर विकास की कई कवायदों का जिक्र किया। उन्होंने हर गांव में बिजली पहुँचाने, स्कूल-खोलने, बैंक सेवाओं का विस्तार और बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित करने के सरकारी इरादे पर भी बल दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि बस्तर के बच्चे कलेक्टर और डॉक्टर बनें और क्षेत्र के विकास के लिये केंद्र व राज्य एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बस्तर के आंतरिक इलाकों को शहर से जोड़ने वाली बस सेवा का शुभारम्भ किया है। उन्होंने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि इस सेवा से करीब 250 गांव जुड़ेंगे जिससे लोगों को शहरी सुविधाएँ और बाजारों तक आसान पहुँच होगी।

इस प्रकार के कदमों को श्री शाह ने नक्सलवाद के जनाधार को तोड़ने वाली योजनाओं का हिस्सा बताया और ग्रामीण समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने का आग्रह किया। सभा में उन्होंने बार-बार इस नारे को दोहराया कि हम हर एक गांव को नक्सल-मुक्त करेंगे। साथ ही उन्होंने 31 मार्च 2026 की समय-सीमा पर सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहरायी।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद विकास की लड़ाई के कारण उपजा मुद्दा है और विकास पहुँचाकर ही इसका अंत किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देशों पर मेडिकल स्टोर्स पर एफडीए की छापेमारी

पथ प्रवाह, देहरादून

बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशभर में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए.) की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। यह अभियान हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा (कफ सिरप) के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद शुरू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इसे जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए तत्परता से कार्रवाई प्रारंभ की है।

केंद्र की एडवाइजरी पर तुरंत कार्रवाई

स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) डॉ. आर राजेश कुमार ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि भारत सरकार की एडवाइजरी को प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य से बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि औषधि निरीक्षक चरणबद्ध तरीके से

कफ सिरपों के नमूने एकत्र करें और उनकी गुणवत्ता की प्रयोगशाला जांच कराएं, ताकि किसी भी दोषपूर्ण या हानिकारक दवा को बाजार से तत्काल हटाया जा सके।

बच्चों के लिए प्रतिबंधित सिरप न लिखें डॉक्टर

डॉ. आर. राजेश कुमार ने प्रदेश के सभी चिकित्सकों से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी का संज्ञान लेते हुए वे बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप न लिखें। डॉ आर. राजेश कुमार ने कहा यदि चिकित्सक इन सिरपों को लिखेंगे तो मेडिकल स्टोर भी उन्हें बेचेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर स्वयं भी जिम्मेदारी दिखाएं और प्रतिबंधित दवाओं से परहेज़ करें।

कौन-सी दवाएं प्रतिबंधित हैं

भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार – दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा नहीं दी जानी चाहिए। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में इन दवाओं का सामान्य उपयोग अनुशंसित नहीं है।

केवल विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह, सही खुराक और न्यूनतम अवधि के लिए ही इनका उपयोग किया जा सकता है। सरकार ने विशेष रूप से De&tromethorphan युक्त सिरप और Chlorpheniramine Maleate + Phenylephrine Hydrochloride संयोजन वाली दवाओं को चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित किया है।

प्रदेशभर में छापेमारी और सैंपलिंग अभियान

प्रदेश में इस आदेश के बाद अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी के नेतृत्व में राज्यभर में युद्धस्तर पर छापेमारी की जा रही है। स्वयं अपर आयुक्त ने देहरादून के जोगीवाला, मोहकमपुर समेत कई क्षेत्रों में औषधि दुकानों का निरीक्षण किया। सभी जिलों में औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस माह के भीतर सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और खुदरा दुकानों से सिरपों के नमूने लेकर प्रयोगशाला परीक्षण करवाएँ। ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि एफ.डी.ए. की टीमें प्रदेशभर में सक्रिय हैं। यदि किसी भी स्तर पर दोष पाया गया तो संबंधित कंपनी या विक्रेता के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त संदेश - जनस्वास्थ्य सर्वोपरि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रदेश में बिकने वाली हर दवा सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाली हो। जनस्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और बच्चों की सुरक्षा पर किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार प्रदेश में औषधि गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को और सुदृढ़ करने की दिशा में भी काम कर रही है।

बच्चों की दवा में लापरवाही अस्वीकार्य- डॉ. धन सिंह रावत

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा राज्य सरकार केंद्र की एडवाइजरी का पूरी गंभीरता से पालन कर रही है। बच्चों की दवाओं से जुड़ी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी चिकित्सकों और औषधि विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिबंधित सिरप को न लिखें और न बेचें। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

जनता से अपील - डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को दवा न दें

एफ.डी.ए. ने राज्यभर में कफ सिरप की सैंपलिंग शुरू कर दी है। अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने जनता से अपील की है कि वे बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। यदि किसी दवा के सेवन से कोई प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दे तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल से संपर्क करें।

यूकेएसएसएससी परीक्षा का एक मुन्ना भाई गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे परीक्षा देने का प्रयास

पथ प्रवाह, देहरादून

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की परीक्षा में फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे शामिल होने की साजिश रचने वाला आरोपी आखिरकार दून पुलिस के शिकंजे में आ गया। अभिलेखों में हेराफेरी कर एक ही परीक्षा के लिए तीन अलग-अलग केंद्रों से आवेदन करने वाले इस अभियुक्त को पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा गठित विशेष टीम ने आयोग से प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की करतूत का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि सुरेन्द्र कुमार पुत्र सलेक कुमार निवासी कनकपुर, भोजपुर मोदीनगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) ने आगामी सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 / सहायक विकास अधिकारी परीक्षा हेतु फर्जी प्रमाणपत्रों के सहारे तीन मोबाइल नंबरों से तीन अलग-अलग आवेदन

किए थे।

पुलिस की गोपनीय जांच में खुली पोल

आयोग द्वारा संदिग्ध अभ्यर्थी की सूचना मिलने पर एसएसपी देहरादून ने गोपनीय जांच के आदेश दिए। जांच में पुष्टि हुई कि सुरेन्द्र कुमार ने टिहरी, हरिद्वार और देहरादून तीनों जिलों के परीक्षा केंद्रों से अलग-अलग आवेदन जमा कराए थे। उसके दस्तावेज़ों की बारीकी से जांच में पाया गया कि उसने परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त करने की नीयत से फर्जी प्रमाणपत्रों का प्रयोग किया था।

फर्जीवाड़े की कहानी

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह मूल रूप से कनकपुर भोजपुर मोदीनगर (गाजियाबाद) का निवासी है और वर्तमान में पिलखुआ, हापुड़ में पत्नी और माता-पिता के साथ रहता है। वह एक निजी स्कूल में अध्यापक है और उसकी पत्नी उसी स्कूल में शिक्षिका है।

सुरेन्द्र की वास्तविक जन्मतिथि 1 अप्रैल 1988 है, लेकिन सरकारी नौकरी की उम्र सीमा निकलने पर उसने गाजीपुर से 2012 में दोबारा हाईस्कूल और 2014 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी, जिसमें जन्मतिथि 1 जनवरी 1995 दर्शाई। इसके अलावा उसने राजस्थान से 2012 में और सोलन (हिमाचल प्रदेश) से 2018 में दो बार बी.ए. की डिग्री भी हासिल की।

योजनाबद्ध तरीके से उम्र कम दर्शाते हुए उसने तीन जिलों से आवेदन किया ताकि किसी न किसी केंद्र पर प्रवेश मिल सके। आरोपी के खिलाफ थाना रायपुर पर मु.अ.सं. 311/25, धारा 318(4), 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

एसएसपी देहरादून के निर्देश पर कार्रवाई तेज

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने इस फर्जीवाड़े के पूर्ण अनावरण हेतु एसओजी प्रभारी निरीक्षक मुकेश त्यागी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की थी। टीम ने सुरेन्द्र कुमार को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की और उसके कृत्यों की पुष्टि के बाद विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी।

एक लाख का इनामी महताब पुलिस एनकांउटर में हुआ ढेर

पथ प्रवाह संवाददाता।

मुजफ्फरनगर। थाना बुढ़ाना और थाना शाहपुर पुलिस की संयुक्त टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया। मारे गए बदमाश की शिनाख्त महताब के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक शातिर महताब पर एक लाख का इनाम घोषित था। इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

पुलिस के मुताबिक देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि दो कुख्यात बदमाश किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्धों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग से उपनिरीक्षक ललित कसाना और आरक्षी अलीम घायल हो गए। इसके अलावा थाना प्रभारी बुढ़ाना और थानाध्यक्ष शाहपुर की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगीं। अभियुक्त मोटरसाइकिल छोड़कर पास के बंद ईंट-भट्टे में घुस गए और वहां से भी पुलिस पर लगातार फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक अपराधी महताब पुत्र अब्बास, निवासी ग्राम सौंटा रसूलपुर, थाना थानाभवन (शामली) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कुछ देर बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक महताब शातिर किस्म का बदमाश और थाना बुढ़ाना का वांछित अपराधी था। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के 18 से अधिक मामले दर्ज थे। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

शहीद सम्मान यात्रा 2.0% का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने फ्लैग ऑफ कर किया शुभारम्भ

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला मुख्यालय परिसर में शहीद सम्मान यात्रा 2.0% का फ्लैग ऑफ कर किया रवाना। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि जनपद के दो शहीद सैनिकों के आश्रितों गीता सैनी शहीद हवलदार सोनित कुमार सैनी निवासी ग्राम-धनौरा रुड़की एंव कविता चौधरी पत्नी शहीद नायक प्रदीप कुमार निवासी ग्राम-गदरजुडा, मंगलौर, रुड़की को प्रदेश सरकार की तरफ से 05 अक्टूबर को गढ़वाल राईफल्स रेजीमेंट सेन्टर लैंसडाउन में शहीद सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा वीर नारियों/आश्रितों को ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया जायेगा। कार्यक्रम हेतु प्रदेशभर में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की शुरूआत दिनांक 25 सितम्बर 2025 से 04 अक्टूबर 2025 तक की गई, जिसमें शहीद सैनिकों के घर-आंगन की मिटट्री एकत्रित की गई। उन्होंने कहा कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा शहीद सैनिकों के आश्रितों को उनके आवास से विभागीय वाहन के द्वारा रोशनाबाद लाया गया,

जहां से फ्लैग आफ कार्यक्रम के उपरान्त वीर नारियों एंव उनके आश्रितों को लैंसडाउन के लिये रवाना किया गया। कार्यक्रम के दौरान विंग कमांडर (से.नि.) डॉ. सरिता पंवार ने बताया कि प्रथम शहीद सैन्य सम्मान यात्रा के उपरान्त प्रदेश में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में उनके घर-आंगन की मिट्टी एकत्रित किये जाने हेतु शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारम्भ प्रत्येक उस जनपद में किया गया, जहां शहीद सैनिक परिवार निवासित है। उन्होंने कहा कि जनपद हरिद्वार के 02 शहीद सैनिक कमशः शहीद नायक प्रदीप कुमार निवासी ग्राम-गदरजुड़ा, ब्लाक-नारसन, जनपद हरिद्वार, जो कि 27 अक्टूबर 2023 को सिक्किम क्षेत्र में शहीद हुए थे एंव शहीद हव0 सोनित कुमार सैनी निवासी ग्राम-धनौरी, ब्लाक-रूड़की जनपद हरिद्वार, जो कि दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को अरूणांचल प्रदेश के डुकुमपानी क्षेत्र में शहीद हुए थे, उनके घर-आंगन की मिट्टी एकत्रित कर लैंसडाउन के लिये रवाना किया गया।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी दीपेन्द्र सिंह नेगी, जिला सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास अधिकारी एंव समस्त कार्मिक, 31 यूके एन.सी.सी. बटालियन से सूबेदार सुभाष सिंह, हवलदार चुख बहादुर, पूर्व सैनिकों, गणमान्य व्यक्तियों तथा ब्लाक प्रतिनिधियों आदि भी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नगर निकायों की आमदनी बढ़ाने को दिए सुझाव

पथ प्रवाह, नवीन चौहान

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उसकी आय के संसाधनों में बढोत्तरी करने पर जोर दिया।

डीएम ने निर्देशित किया कि सभी नगर निकाय अपने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाएं। पालिका की दुकानों पर चल रहे कम दामों को मार्केट रेट के अनुसार समायोजित किया जाए और सभी नीलामियां नियमानुसार व पारदर्शिता से आयोजित की जाएँ। साथ ही नियम के विरुद्ध विज्ञापन जारी न करने और निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ही विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शनिवार को जिला कार्यालय सभागार में नगर निकायों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को सफाई, आय वृद्धि, आवारा पशु प्रबंधन एवं सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु दिशा निर्देश दिए।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आवारा पशुओं की समस्या पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि कुत्तों, बंदरों और गौवंशीय पशुओं के नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवारा गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाया जाए और आवारा कुत्तों का नियंत्रित बध्याकरण किया जाए।

सफाई व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि बाजार क्षेत्रों में दिन में दो बार सफाई की जाए, डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह सुनिश्चित किया जाए और गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों तथा ठेले वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाए। कूड़े का निस्तारण उचित रूप से किया जाना चाहिए और सभी अधिशासी अधिकारी एक सप्ताह के भीतर संबंधित डंपिंग यार्ड का निरीक्षण करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह भी कहा कि कार्यालय आने से पहले फील्ड में जाकर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लें।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने तकनीकी निगरानी पर भी जोर देते हुए कहा कि सभी कूड़ा वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएँ और वाहनों की मॉनिटरिंग स्वयं अपने मोबाइल से की जाए।

सार्वजनिक सुविधा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि खराब स्ट्रीट लाइट्स की तुरंत मरम्मत की जाए, दीपावली के दौरान पटाखा बाजारों के संचालन हेतु अभी से संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए।

डीएम मयूर दीक्षित ने सेवाओं की गुणवत्ता पर भी जोर देते हुए कहा कि यूसीसी अंतर्गत विवाह पंजीकरण जैसी सेवाओं में निर्धारित समय सीमा के भीतर डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाएँ, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, नगर आयुक्त आर.के. तिवारी सहित अन्य अधिशासी अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि डीएम मयूर दीक्षित के कड़े और स्पष्ट निर्देश नगर निकायों को आर्थिक सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम है। उनके निर्देशात्मक फैसलों से यह सुनिश्चित होगा कि हरिद्वार नगर निकायों की सेवाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और सार्वजनिक अनुशासन को और मजबूती मिले।

डीपीएस रानीपुर में शिक्षकों के लिए ज्ञानवर्धक कार्यशाला

सीबीएसई सीओई देहरादून के तत्वावधान में 'शिक्षण पद्धति एवं परिणाम संवर्धन' पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित

शिक्षा में नवाचार और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर केंद्रित प्रशिक्षण, 60 शिक्षकों ने लिया भाग

पथ प्रवाह, हरिद्वार

डीपीएस रानीपुर में शनिवार को सीबीएसई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) देहरादून के तत्वावधान में ÷शिक्षण पद्धति एवं परिणाम संवर्धन÷ विषय पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 60 शिक्षकों ने सहभागिता की।

कार्यशाला का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉ. अनुपम जग्गा एवं अतिथि विशेषज्ञों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित श्रीमती रश्मि गोयल, प्रधानाचार्य द सेपियंस स्कूल देहरादून, एवं राजेश देवरानी, प्रधानाचार्य माउंट लिट्रा जी स्कूल, रूड़की ने शिक्षण प्रक्रिया के विविध पहलुओं पर विस्तृत विचार साझा किए।

पहला सत्र- शिक्षण पद्धति की गहराई और प्रयोगशीलता

कार्यशाला के प्रथम सत्र में श्रीमती रश्मि गोयल ने पाठ योजना निर्माण, शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति और कक्षा में व्यवहारिक दृष्टिकोण के प्रयोग पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि एक प्रभावी शिक्षक बच्चों के मानसिक विकास को समझते हुए शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाता है। उन्होंने शिक्षकों को विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक मजबूती और भावनात्मक संवर्धन के लिए उपयोगी उपाय बताए।

दूसरा सत्र- परिणामोन्मुख शिक्षण और छात्रों से संवाद

दूसरे सत्र में राजेश देवरानी ने बच्चों में आत्मविश्वास और सक्रिय सहभागिता को बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि हर शिक्षक को पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा आरंभ करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विषयवस्तु विद्यार्थियों तक सही रूप में पहुँचे। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे छात्रों में सक्रिय श्रवण, आत्म-अभिव्यक्ति, भावनात्मक समझ और तनाव प्रबंधन की क्षमता विकसित करें।

प्रायोगिक गतिविधियाँ और प्रेरक संदेश

दोनों विशेषज्ञों ने पाठ-योजना संयोजन और कक्षा के सकारात्मक वातावरण निर्माण से जुड़ी प्रायोगिक गतिविधियाँ भी कराईं।

प्रधानाचार्य डॉ. अनुपम जग्गा ने कहा कि प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है कि वह छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से सुरक्षित वातावरण में सीखने का अवसर दे। उन्होंने सीबीएसई सीओई देहरादून एवं दोनों विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी कार्यशालाएँ शिक्षण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाती हैं।

खानपुर: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अंकित कुमार निलंबित

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जिले में प्रशासनिक अनुशासन को ताक पर रखकर एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा और गाली-गलौच करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अंकित कुमार को निलंबित कर दिया है।

आदेश में बताया गया है कि कार्यालय ने 12 अगस्त 2025 को अंकित कुमार से स्पष्टीकरण मांगा था। यह स्पष्टीकरण उस ऑडियो क्लिप के संबंध में मांगा गया जिसमें

उन्हें किसी व्यक्ति से गाली-गलौच करते हुए सुना गया। बावजूद इसके, पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने कार्यालय को कोई जवाब नहीं दिया। इस अनुशासनहीनता और सरकारी कर्मचारियों के आचार नियमों के उल्लंघन को गंभीर माना गया है। निलंबन के दौरान अंकित कुमार को सहायक विकास अधिकारी (पं.) बहादराबाद के कार्यालय में तैनात किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता, अर्ध औसत वेतन एवं मंहगाई भत्ता दिया जाएगा। अन्य भत्ते केवल तभी मान्य होंगे जब वे यह प्रमाणित करेंगे कि वे किसी अन्य सेवायोजन या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो अंकित कुमार को दीर्घकालीन दंड भी मिल सकता है। इस संबंध में पृथक रूप से आरोप पत्र जारी किया जाएगा और जांच प्रक्रिया चल रही है।

मौसम का अभी फिर बदलेगा मिजाज, दो दिन भारी बारिश की संभावना

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। मौसम का मिजाज अभी फिर से बदलेगा। मौसम विभाग ने अगामी दिनों के संभावित मौसम का बुलेटिन जारी किया है, जिसमें हरिद्वार में 6 व 7 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जतायी गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार 6 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है जिसके चलते औरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 7 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जनपदों के लिए भी अगामी पांच दिनों में मौसम कैसा रहेगा ये बुलेटिन के माध्यम से बताया गया है।

मौसम विभाग द्वारा 6 व 7 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी करने के बाद स्थानीय प्रशासन ने भी सर्तक रहने के निर्देश दिये हैं। प्रशासन ने इस संबंध में मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी को अपनाने की सलाह दी है। यात्रा पर निकले लोगों से खासतौर पर सावधानी बरतने की अपील की गई है।

संपादकीय

ऐतिहासिक कदम या अधूरा समाधान

उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने राज्य के 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने का निर्णय निस्संदेह एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। इस कदम से उत्तराखंड के ग्रामीण, पर्वतीय और सीमांत इलाकों में अब सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू होगी। वर्षों से जिन क्षेत्रों में पुलिस का प्रत्यक्ष नियंत्रण सीमित था, वहां अब अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और न्याय की उपलब्धता सुदृढ़ हो सकेगी। यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेशों तथा मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप राज्य की कानून व्यवस्था को स्थायी मजबूती देने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को प्रदेश की जनसुरक्षा को नई दिशा देने वाला कदम बताया है। उनके अनुसार, इस पहल से जनता में सुरक्षा भाव और शासन के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अब पुलिस की उपस्थिति, निगरानी और जवाबदेही बढ़ेगी। इससे अपराधों की रोकथाम, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, और न्याय तक सरल पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी। नीतिगत स्तर पर यह निर्णय स्वागत योग्य है, परंतु व्यवहारिक स्तर पर इसकी चुनौतियाँ भी उतनी ही गंभीर हैं। राज्य के पास पहले से ही पुलिस बल की कमी एक बड़ी समस्या है। 1983 गांवों में नियमित पुलिस व्यवस्था लागू करने के लिए पुलिस चौकियों, थानों, वाहनों, संचार तंत्र और कर्मियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता होगी। पुलिसकर्मियों के पद सृजन की आवश्यकता। इतने बड़े विस्तार को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पदों का सृजन और नई नियुक्तियाँ करनी होंगी। मौजूदा बल पहले से ही सीमित संसाधनों और अत्यधिक कार्यभार से जूझ रहा है। राज्य के पुलिसकर्मियों के मनोबल से जुड़ा सबसे बड़ा प्रश्न है – 4600 ग्रेड पे का है। वर्षों से यह मांग लंबित है और पुलिस बल के मनोबल पर सीधा असर डाल रही है। जब राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करती है, तब यह भी आवश्यक है कि जो बल इसे लागू करेगा, उसका आर्थिक और सामाजिक सम्मान भी सुनिश्चित हो। पुलिस एक अनुशासित बल है – जो प्रायः अपनी बात सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी समस्याएं गौण रहें। वेतन, कार्य घंटे, प्रमोशन और संसाधन संबंधी दिक्कतें लंबे समय से जस की तस हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकार पुलिस सुधारों को नीतिगत प्राथमिकता में रखे। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस क्षेत्राधिकार का विस्तार तभी कारगर सिद्ध होगा जब जमीन पर कार्यरत सिपाही से लेकर अधिकारी तक, हर स्तर पर संसाधन, प्रशिक्षण और सम्मान की सुनिश्चितता होगी। एक थका हुआ, उपेक्षित और असंतुष्ट पुलिस बल जनसुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। राज्य सरकार को अब यह देखना होगा कि ÷कानून व्यवस्था की मजबूती सिर्फ आदेशों से नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों के आत्मबल से आती है।÷ 1983 गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल करना उत्तराखंड सरकार की दूरदर्शी सोच का परिचायक है। लेकिन यह निर्णय तभी पूर्ण और प्रभावी माना जाएगा जब इसके साथ पुलिस बल के नए पद सृजित हों, 4600 ग्रेड पे का मुद्दा सुलझे, आवास, उपकरण, प्रशिक्षण और मनोबल की मजबूती के लिए ठोस नीतियां लागू हों। राज्य की कानून व्यवस्था तभी सुदृढ़ होगी जब पुलिस और जनता – दोनों विश्वास और सहयोग के सूत्र में बंधें।सरकार का यह कदम उस दिशा में पहला पड़ाव है, परंतु अंतिम नहीं। अब अगला कदम होना चाहिए – पुलिस व्यवस्था में सुधार, सम्मान और संसाधन का विस्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी युवा हैं। प्रदेश पुलिस के हितों के लिए ठोस कदम उठाएंगे।

जरूरी है राष्ट्र निर्माता के रूप में शिक्षकों का सम्मान

श्वेता गोयल

एक ओर जहां भारत में द्वितीय राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर 5 सितम्बर को 'शिक्षक दिवस' मनाया जाता है, वहीं दुनिया के अनेक देश 5 अक्तूबर को 'विश्व शिक्षक दिवस' मनाते हैं और इस अवसर पर शिक्षकों के सम्मान में दुनियाभर के देशों में तरह-तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दरअसल किसी भी देश के विकास की कल्पना शिक्षा के बिना बेमानी ही है, इसीलिए दुनियाभर के शिक्षकों के महत्व और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए ही विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मूल उद्देश्य विश्वभर में शिक्षण और शिक्षकों के मूलभूत मुद्दों पर चर्चा करना है। वर्ष 1960 के आसपास करीब सभी देशों में शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए 5 अक्तूबर 1966 को 'टीचिंग इन फ्रीडम संधि' को मूर्त रूप दिया गया। इसमें दुनियाभर के शिक्षकों की स्थिति को सुधारने और उन्हें जागरूक करने के लिए एक समझौता पारित किया गया। दरअसल 5 अक्तूबर 1966 को पेरिस में एक कांफ्रैंस का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षकों के अधिकार और जिम्मेदारी सहित उनसे संबंधित कई मुद्दों पर यूनेस्को तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की सिफारिशों को यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था। यूनेस्को और आईएलओ की उस बैठक में शिक्षकों के अधिकारों, जिम्मेदारियों, रोजगार और शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए 1994 में 100 देशों के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र में यूनेस्को की इन सिफारिशों को पारित कर दिया गया। उसी के बाद 5 अक्तूबर 1994 से विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई और तभी से प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को इसे विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष पूरी दुनिया 31वां विश्व शिक्षक दिवस मना रही है।

यूनेस्को द्वारा विश्व शिक्षक दिवस के लिए प्रतिवर्ष एक थीम निर्धारित की जाती है और विश्व शिक्षक दिवस 2025 का आधिकारिक विषय है 'शिक्षण को एक सहयोगात्मक पेशे के रूप में पुनः स्थापित करना'। यूनेस्को का मानना है कि पूरी दुनिया को इस समय वैश्विक स्तर पर शिक्षकों की अभूतपूर्व कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो उनकी कामकाजी परिस्थितियों और स्थिति में गिरावट के कारण और भी गंभीर हो गई है। 2022 में विश्व शिक्षक दिवस 'शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है' थीम के साथ मनाया गया था। दरअसल वैसे तो व्यक्ति जीवनभर सीखता रहता है लेकिन शिक्षक के बिना सही ज्ञान नहीं मिलता, इसीलिए शिक्षक दिवस का विशेष महत्व होता है। 5 अक्तूबर के दिन विश्वभर में 100 से भी ज्यादा देशों में विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर तरह-तरह के आयोजन किए जाते हैं। प्रत्येक देश में इस दिन का अपने-अपने तरीके से स्वागत किया जाता है। कई देशों में तो इस दिन सार्वजनिक अवकाश भी रखा जाता है लेकिन वहां अवकाश के इन पलों को लोग अपने शिक्षकों के साथ किसी न किसी रूप में शेयर करते हैं। सही मायनों में विश्व शिक्षक दिवस महज सार्वजनिक अवकाश नहीं बल्कि एक वैश्विक उत्सव है।

हालांकि भारत सहित कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां शिक्षक दिवस मनाए जाने की तारीख अलग-अलग हैं लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है। चीन में कन्फ्यूशियस के जन्मदिन के अवसर पर 27 अगस्त 1939 को शिक्षक दिवस मनाना आरंभ किया गया था किन्तु 1951 में यह घोषणा वापस ले ली गई और 1985 से 10 सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। रूस में 1994 से 5 अक्तूबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है किन्तु 1965 से 1994 तक अक्तूबर माह के पहले रविवार को यह दिवस मनाया जाता था। ईरान में 2 मई 1980 को प्रोफेसर अयातुल्लाह मोर्तेजा मोतेहारी की हत्या के बाद उसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मलेशिया में शिक्षक दिवस को 'हरि गुरू' के नाम से जाना जाता है, जो 16 मई को मनाया जाता है। वहां 16 मई 1956 को रजाक रिपोर्ट स्वीकृत हुई थी, जिसके आधार पर वहां शिक्षा प्रणाली का चयन हुआ था। उसी दिन को बाद में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। थाईलैंड में 1957 से ही प्रतिवर्ष 16 जनवरी को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उस दिन वहां सभी स्कूलों में अवकाश रहता है। तुर्की में यह दिवस 24 नवम्बर को जबकि अमेरिका में 6 मई को मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में माह के पहले सप्ताह में पूरे सप्ताह तक आयोजन होते हैं।

आस्ट्रेलिया में शिक्षक दिवस अक्तूबर महीने के अंतिम शुक्रवार को मनाया जाता है जबकि अर्जेन्टीना में इस दिवस का आयोजन डोमिनो फास्टिनो सामिएटो की मृत्यु के दिन 11 सितम्बर को किया जाता है। वियतनाम में 1958 में 20 नवम्बर को पहली बार यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों के घोषणा पत्र के रूप में मनाया गया था और 1982 में इसे पुनः नामांकित कर वियतनामी शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया। पेरू में 6 जुलाई 1953 को वहां के राष्ट्रपति मैनुएल ए आड्रिया ने एक अध्यादेश पारित कर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया था जबकि पाकिस्तान में यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन 5 अक्तूबर को ही मनाया जाता है। चिली में 16 अक्तूबर को शिक्षकों के कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसी उपलक्ष्य में वहां 16 अक्तूबर 1977 से इसी दिन शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा जबकि ब्राजील में शिक्षक दिवस का आयोजन 15 अक्तूबर को किया जाता है। दरअसल 15 अक्तूबर 1827 को वहां पेड्रो ने प्राथमिक शिक्षा को नियंत्रित किया था लेकिन अधिकारिक रूप में 15 अक्तूबर को ही शिक्षक दिवस मनाने के लिए मान्यता 1963 में मिली थी। बहरहाल, यूनेस्को का कहना है कि 5 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस घोषित करने से दुनियाभर में सेवारत तमाम शिक्षकों को उनके द्वारा शिक्षा और विकास के क्षेत्र में दिए जा रहे अहम योगदान से लोगों को अवगत कराया जाता है, जिससे आम लोगों को शिक्षकों के बारे में और अधिक समझने का अवसर मिलता है।

भारत को पीओके की पुकार: पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति

दिलीप कुमार पाठक

धर्म के नाम पर पाकिस्तान की स्थापना हुई थी, यही कारण है कि आजतक पाकिस्तान राजनीतिक रूप से स्थायी नहीं है, कोई न कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता ही रहता हैद्य बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के अलगाव के बाद पीओके यानि पाक अधिकृत कश्मीर में हमेशा पाकिस्तान से अलग होने की आवाजें बुलन्द होती रहती हैंद्य अभी कुछ महीनों पहले अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए वहाँ के विद्रोही लोगों ने ट्रेन हाईजैक कर लिया था, खासी मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान की सेना ने वहाँ की विरोधी आवाजों का दमन कर दिया थाद्य पाकिस्तानी सेना ने अब तब पीओके पर दमनपूर्वक जबरन क़ब्ज़ा कर रखा है, अन्यथा वहाँ कई बार भारत में विलय एवं जनमत संग्रह की मांगें उठती रहती हैंद्य अब देखना यह है कि पाकिस्तानी सेना कब तक इन आवाजों को दबा पाती हैद्य अभी हाल फ़िलहाल पीओके में विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से बिजली संकट, महंगे बिल, इंटरनेट ब्लैकआउट, मानवाधिकार उल्लंघन, और आर्थिक उपेक्षा के खिलाफ शुरू हुआ हैद्य जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही हैद्य पाकिस्तानी नेतृत्व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जनता की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने में फेल साबित हो रहा हैद्य पाक अधिकृत कश्मीर में स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना का अत्याचार अब संयुक्त राष्ट्र तक तक पहुंच गया हैद्य वैसे भी पीओके पर जुल्म इतना बढ़ गया है कि वहाँ की चीखें पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी हैं, वो तो भारत सरकार की नीतियों की विफलता है अन्यथा अब तक पीओके भारत का हिस्सा बन चुका होताद्य देश ज़मीन के टुकड़ों पर नहीं बनता बल्कि देश में रहने वाले लोगों के कारण देश बनता है, जहां पाकिस्तान मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर ज़बरदस्ती लोगों पर राज करना चाहता है, हालांकि अब बड़ा कठिन सा प्रतीत हो रहा हैद्य पीओके के राजनीति दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से मांग की है कि ह तुरंत यहां दखल दे और यहां की जनता को पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बचाएद्य 29 सितंबर से चल रहे नागरिकों के प्रदर्शन में अब तक 12 लोग मारे जा चुके हैंद्य एक जान की भी कीमत होती है, पाकिस्तान की सेना को इसका खामियाज़ा ज़रूर भुगतना होगाद्य

स्विटजरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 60वें सेशन के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पार्टी (यूनाइटेड कश्मीर पीपुल नेशनल पार्टी) ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान को कश्मीरियों को मारने, हमारी जमीन और हमारे संसाधनों पर कब्जा करने, हमारे लोगों पर अत्याचार करने और उन्हें खत्म करने का कोई हक नहीं हैद्य पीओके के स्थानीय नेता इस मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने लेकर आए हैं, हालांकि उन्होंने कितना शोषण, दमन झेला है, इसकी कल्पना करना भी असहनीय पीड़ा को सहन करने जैसा हैद्य यूनाइटेड कश्मीर पीपुल नेशनल पार्टी के प्रवक्ता सरदार नासिर अजीज खान ने जिनेवा में कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में कई लोग गायब हो गए हैं, परंतु हाल ही में कश्मीर में जो हो रहा है, उससे लोग अपनी जान को लेकर चिंतित हैं क्योंकि 29 सितंबर से अब तक 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी हैद्य नासिर ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान यहां के लोगों पर क्रूर बल प्रयोग कर रहा है और प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा है जिससे लोग मारे जा रहे हैंद्य सैकड़ों लोग जेल में हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा हैद्य उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जमावड़े के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र उन कश्मीरियों की जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करे जो पाकिस्तानी कब्जे में रह रहे हैं।

विदेश में देश की छवि खराब करना उनकी आदत

कांतिलाल मांडोत

कांग्रेस सांसद और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कोलम्बिया के ईआईए विश्वविद्यालय के एक संवाद कार्यक्रम में कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हमला है।भारतीय सरंचना में कमी बताते हुए कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है।राहुल देश मे किसी भी राज्य के चुनाव के पूर्व ओछी राजनीति करने के लिए एवं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करने विदेश जाते है।भारत मे उनकी कोई नही सुनता है।इसलिए हरबार विदेश में भारत की बुराई या सतारूढ़ सरकार की आलोचना करते है।भारत दुनिया मे सबसे बड़ा लोकतंत्र है।राहुल गांधी इतने ही नासमझ तो नही होने चाहिए, जोकि अपने देश की बुराई विदेश में जाकर करते है।भारत की विदेश नीति दुनिया मे सबसे अच्छी है।भारत के दुनिया के कई देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बब्ध है।भारत की दुनिया जयकारा लगाती है।लेकिन भारत की आलोचना कर सतारूढ़ सरकार का कोई नुकसान नही कर रहे है,बल्कि अपनी ही पार्टी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे है।विदेश में भारत को बदनाम करने औरभारत की छवि को घुमिल करने का कार्य कर रहे है।कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत सतारुढ़ पार्टी को हटाने के लिए किया जा रहा षडयंत्र कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है।राहुल गांधी को यह सब करने के लिए मजा आता है।विदेश में राहुल ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया।राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बोस्टन में हमला बोला और चुनाव आयोग को घेरते हुये उन्होंने कम्प्रोमाइजड बताया।राहुल गांधी कांग्रेस के शायद पहले नेता है,जिन्होंने विदेश में सतारूढ़ सरकार पर कई बार हमलावर हुए है।कांग्रेस नेता राहुल जानबूझकर भाजपा को बदनाम कर रहे है।क्योंकि भारत मे उनके आरोप कोई बड़ा परिवर्तन नही करता है।इसलिए विदेश में जाकर छात्र छात्राओं के समक्ष कटुता उजागर करते है।भाजपा ने विदेश यात्रा पर हमला बोलते हुए भाजपा ने भारत बदनाम यात्रा कहा है।कांग्रेस अपनी नाकामयाबी का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रही है।कांग्रेस के लिए देश मे कई अवसर आए और चले गए, लेकिन कांग्रेस उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है।2024 का चुनाव होने के बाद चिंताग्रस्त कांग्रेस ने राहुल को विदेशी यात्रा के लिए रवाना किया।पिछले वर्ष अमेरिका के प्रेस क्लब में राहुल ने भारतीय लोकतंत्र पर बड़ा हमला बोला और कहा कि भारत में पिछले दस सालों में ब्रोकन हुआ था यानी टूटा है।अब वह लड़ रहा है।दस सालों के बाद कांग्रेस को लोकसभा में विपक्ष का पद प्राप्त हुआ है।क्योकि कांग्रेस 99 सीटे जितने के बाद कांग्रेस ने उन्हें विपक्ष को घेरने के लिए राहुल को अध्यक्ष का पद दिया गया।जवाहरलाल नेहरू से राजीव गांधी तक एक ही पिक पर कांग्रेस कार्य कर रही है।कांग्रेस की नीतियां चुनाव में प्रत्याशियों को पीछे करने के लिए मजबूर करती है।राहुल ने यह सवाल कहकर उनकी और कांग्रेस की मूल भावना को ही उजागर कर दिया था।उन्होंने कहा कि 2014 से 2019में चुनाव हुआ उसमे मतदाताओ ने वोट नही डाला था।यह राहुल की भावना ही दर्शाती है।कांग्रेस विपक्षी दल है।सरकार ने सवाल करने का पूरा हक है।लेकिन कोई भी मुद्दा तथ्यात्मक होना चाहिए।बेबुनियाद बयानबाजी से कांग्रेस को ही नुकसान होता दिखाई दे रहा है।राहुल बिना आधार का आरोप लगाकर सुर्खियों में रहना चाहते है।ब्रसेल्स के यूरोपियन यूनियन में राहुल ने कहा था कि फुल स्केल एसॉल्ट हो रहा है।यानी भारतीय संस्थाओ की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था।इतना ही नही आइडियाज ऑफ इंडिया सम्मेलन में राहुल ने भारतीय संस्थाओं को परजीवी कहा था।2022 में राहुल ने भारतीय संस्थाओ पर अंगुली निर्देश कर राहुल ने फिर भारत को बदनाम करनी की कोशिश की गई।2018 में यूके औरजर्मनी में राहुल गांधी ने कहा था प्रधानमंत्री देशभक्त नही है।देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री पर गम्भीर आरोप था।नोटबन्दी को लेकर कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री होते तो इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देते।यह बयान राहुल ने मलेशिया में नोटबन्दी को लेकर दिया था।अभिव्यक्ति की आजादी के स्वतंत्र अभिगम को लेकर बेबुनियाद आरोपो की झड़ी लगाई जा रही है।सिंगापुर में कुआन यूपब्लिक पॉलिसीने राहुल ने 2018 में आरोप लगाया और कहा कि भारत मे डर और नफरत का माहौल है।यह सवाल अंतराष्ट्रीय मंच पर छवि को खराब करने का माहौल था।भारत मे तो सप्ताह में आरोपो की झड़ी लगती ही है।लेकिन विदेश में राहुल हरदम आरोप लगाने के लिए ही भेजे जाते है।2018 में बहरीन में राहुल ने अपने भाषण के दौरा हढ्ढक्रसम्मेलन में मन की भड़ास निकालते हुए कहा भारत मे नफरत फैलाने में सरकार व्यस्त है और बेरोजगारी को रोकने में भाजपा सरकार नाकाम रही है।देश की छवि को घूमिल करते राहुल ने अमेरिका के बर्कडे स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि भारत मे सरकार केवल सौ टॉप कम्पनियो के लिए काम कर रही है।भारत की फ्री स्पीच पर संदेह पैदा करते हुए कहा कि भारत मे अब सहनशीलता नही रही है।2017 में अमेरिका में राहुल ने कहा कि भारत अब वह नही रहा है।देश की छवि को खराब करने के लिए विदेश जा रहे राहुल गांधी भले ही अपने मन की भड़ास निकालने में सफल हो जाते रहे है।लेकिन उनके भारत विरोधी बयान देशवासियों के लिए कड़वे घूंट के समान है।कोई क्यो अपने देश की निंदा सुनने के लिए तैयार होगा।राहुल को मंथन करने की आवश्यकता है।भारत की छवि खराब करने की कांग्रेस कुतर्क का सहारा ले रही है।वैसे वैसे मोदी की छवि निखर रही है।राहुल के शब्दों का कोई कर्क नही पड़ता है।अगर राहुल के शब्दों को लोग समझकर मानते करते तो देश मे सरकार इनकी बनती?राहुल को चाहिए कि देश की बुराई विदेशो में नही करे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की 50वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का किया उद्घाटन

पथ प्रवाह, संवाददाता - देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में 50वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता 10 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें देशभर के 28 राज्यों से 54 टीमें और एक हजार से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहली बार उत्तराखंड में सब-जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राज्य के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, धैर्य, अनुशासन और टीम भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया मूवमेंट' जैसे अभियानों ने देश में खेलों के प्रति नई चेतना जगाई है और आज भारत खेल के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद तेजी से ÷खेलभूमि÷ के रूप में पहचान बनाई है। राज्य में 517 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों के साथ स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू किया जाएगा। साथ ही, हल्द्वानी में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार की नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों के हित में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी, खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, खेल किट, राज्य स्तरीय पुरस्कार और चार प्रतिशत खेल कोटा की बहाली जैसी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये की सम्मान राशि भी दी गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून में बास्केटबॉल प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना के लिए जिलाधिकारी को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हल्द्वानी में निर्माणाधीन खेल विश्वविद्यालय के पास बास्केटबॉल प्रशिक्षण अकादमी विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि खेल विभाग को बास्केटबॉल सहित अन्य खेलों की नियमित प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को निरंतर अवसर मिल सकें।

समारोह में विधायक खजान दास, उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव कुलविंदर सिंह गिल, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आदित्य चौहान, मंदीप सिंह ग्रेवाल सहित अनेक खेलप्रेमी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

परेड ग्राउंड का माहौल इस दौरान जोश और उत्साह से भर उठा, जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बास्केटबॉल उछालकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ÷उत्तराखंड के युवा खेलों में नई पहचान बना रहे हैं, और हमारा संकल्प है कि हर जिले को खेल प्रतिभा का केंद्र बनाया जाए।

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून में 315 प्रशिक्षु हुए दीक्षित

पथ प्रवाह, संवाददाता - देहरादून

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई), देहरादून में शनिवार को 2024-25 सत्र के प्रशिक्षुओं के लिए चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली से आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल दीक्षांत समारोह के सीधा प्रसारण के साथ हुई।

कार्यक्रम में एनएसटीआई देहरादून के विभिन्न ट्रेडों से उत्तीर्ण कुल 315 प्रशिक्षुओं को भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तराखंड के निदेशक गौरव लांबा ने प्रमाण पत्र प्रदान किए।

मुख्य अतिथि गौरव लांबा ने प्रशिक्षुओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कौशल भारत अभियान के तहत प्रशिक्षु देश की आत्मनिर्भरता की नींव को मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उद्योग जगत में प्रशिक्षित युवाओं की बड़ी मांग है और यह प्रशिक्षु अपने कौशल को उद्योग, स्टार्टअप और उद्यमिता से जोड़कर समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

एनएसटीआई देहरादून के प्राचार्य एवं आईएसडीएस उपनिदेशक ज्ञान प्रकाश चौरसिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि संस्थान न केवल तकनीकी दक्षता प्रदान करता है, बल्कि युवाओं को रोजगारोन्मुखी और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित करता है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से आह्वान किया कि वे अपने कौशल का उपयोग समाज के कल्याण और राष्ट्र निर्माण में करें।

इस अवसर पर आरडीएसडीई उत्तराखंड के आईएसडीएस अधिकारी आर्यन जांगड़ा, गजेंद्र कोली और इंद्रपाल सिंह उपस्थित रहे। एनएसटीआई देहरादून के संकाय सदस्यों में नरेश कुमार, आर.पी. आर्य, जे.एस. गांधी, श्रीमती रंजिनी कुमार और मनीष ममगाईं सहित समस्त कर्मचारी और प्रशिक्षु समारोह में शामिल हुए।

समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। प्रशिक्षुओं ने समूह छायाचित्रों के माध्यम से इस विशेष दिन की यादों को संजोया। पूरे आयोजन में उत्साह, उपलब्धि और आत्मविश्वास का वातावरण झलकता रहा – जो कौशल भारत से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

डाक विभाग देहरादून 6 से 10 अक्टूबर तक मनाएगा राष्ट्रीय डाक सप्ताह

पथ प्रवाह, संवाददाता - देहरादून

डाक विभाग, देहरादून परिमंडल द्वारा इस वर्ष भी 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। यह सप्ताह न केवल डाक सेवाओं की परंपरा और प्रगति का प्रतीक है, बल्कि तकनीकी नवाचार, वित्तीय समावेशन और नागरिक सेवा के संगम का भी उत्सव है।

राष्ट्रीय डाक सप्ताह का उद्देश्य आम नागरिकों, व्यवसायियों और युवाओं को डाक विभाग की आधुनिक सेवाओं और तकनीकी प्रगति से परिचित कराना है। यह आयोजन विभाग की जनसेवा से जनविश्वास की परंपरा को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

06 अक्टूबर–'प्रौद्योगिकी दिवस' से होगी शुरुआत

सप्ताह का शुभारंभ प्रौद्योगिकी दिवस के साथ होगा। इस दिन डाकघरों में तकनीक आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें ग्राहकों और कर्मचारियों से उनके अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि तकनीकी सुधारों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

07 अक्टूबर – वित्तीय समावेशन दिवस (राष्ट्रीय डाक दिवस)

दूसरे दिन वित्तीय समावेशन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान डाक चौपालों का आयोजन कर ग्राहकों को पीएलआई., आरपीएलआई और डाक बचत योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही नए खातों के पंजीकरण किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक नागरिक वित्तीय सेवाओं की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

08 अक्टूबर – फिलैटली दिवस एवं नागरिक केंद्रित सेवाएं दिवस

तीसरे दिन फिलैटली दिवस के अवसर पर विद्यालयों में दीनदयाल स्पर्श छात्रवृत्ति योजना और ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही डाक टिकट संग्रह प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों और युवाओं में फिलैटली के प्रति रुचि बढ़ाई जाएगी।

इसके अतिरिक्त, 35 उपमंडलों में प्रत्येक दो विद्यालयों में आधार पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे, ताकि छात्र-छात्राओं को पहचान सेवाओं से जोड़ा जा सके।

09 अक्टूबर – विश्व डाक दिवस का विशेष आयोजन

विश्व डाक दिवस के अवसर पर सभी डाकघरों में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (क्क) के बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए जाएंगे। कर्मचारियों में उत्साह और सहभागिता बढ़ाने के लिए पोस्टाथॉन वॉक रिले का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी संचालित होगा। मुख्य डाकघर, देहरादून में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल की अध्यक्षता में प्रेस मीट आयोजित की जाएगी, जिसमें यूपीयू अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता 2025 के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

10 अक्टूबर–ग्राहक दिवस के साथ होगा समापन

सप्ताह का समापन ग्राहक दिवस के रूप में होगा। इस दिन डाकघरों में ग्राहक व्यवहार आधारित नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से डाक विभाग और जनता के बीच विश्वास, सहयोग और पारदर्शिता को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा।

एक नजर

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का ऐतिहासिक कदम- उत्तराखंड के 1983 राजस्व गांवों में पुलिस हरदम

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने की घोषणा की। यह कदम ग्रामीण और सीमांत इलाकों में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, अपराधों पर त्वरित नियंत्रण और न्याय की सुनिश्चितता के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब इन गांवों में सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू होगी, जिससे जनता की सुरक्षा और विश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से पुलिस का जवाबदेह और प्रभावी ढांचा मजबूत होगा और सामाजिक वातावरण अधिक सुरक्षित एवं स्वच्छ बनेगा। सरकार के अनुसार, यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेशों और पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप लिया गया है। इसके लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधों पर तेजी से नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सशक्त बनाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। जनता का सहयोग इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाएगा। यह निर्णय प्रदेश के कानून व्यवस्था और सुरक्षा ढांचे में नए युग की शुरुआत करता है, जिसमें ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों तक पुलिस की पहुँच सुनिश्चित होगी और अपराध पर लगाम कसी जाएगी।

स्वामी दर्शनानन्द इंस्टिट्यूट में 'मौसम परिवर्तन एवं नदियाँ' विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला

पथ प्रवाह, हरिद्वार। स्वामी दर्शनानन्द इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के तत्वावधान में ÷मौसम परिवर्तन एवं नदियाँ÷ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी, न्यायिक सदस्य, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी दर्शनानन्द गुरूकुल के विद्यार्थियों द्वारा शंखनाद एवं मंत्रोच्चारण के साथ मुख्य अतिथि के स्वागत और अभिनंदन से हुई। तत्पश्चात सभी सम्मानित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। संस्थान की निदेशक डॉ. जयलक्ष्मी ने मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी का स्वागत रुद्राक्ष माला, शॉल और पौधा भेंट कर किया। विशिष्ट अतिथि श्री रमनकांत, अध्यक्ष, भारतीय नदी परिषद का स्वागत स्वामी विरक्त देव ने किया। प्रदूषण अधिकारी राजेन्द्र कठैत का अभिनंदन प्रधानाचार्य अशोक गौतम ने किया जबकि विकास त्यागी, कार्यपालक अभियंता, उत्तरी गंग नहर, हरिद्वार एवं रुड़की का स्वागत स्वामी मुकुंद देव ने किया। अपने संबोधन में माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी ने कहा कि आज पर्यावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण मानव द्वारा एनजीटी के दिशा-निर्देशों की अनदेखी है।

अंतरराष्ट्रीय मिशन रेबीज़ के साथ मिलकर लहित एनिमल वेलफेयर टीम का संकल्प 'रेबीज़ फ्री उत्तरकाशी' की ओर बड़ा कदम

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। जिले में पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत लहित एनिमल वेलफेयर टीम ने एक और सराहनीय पहल की है। टीम ने अब अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन 'मिशन रेबीज़' (स्ब्ध्ह्यह्यद्वश्ठु ऋड्डद्बद्गह्य) के साथ हाथ मिलाकर उत्तरकाशी को रेबीज़-फ्री बनाने का संकल्प लिया है।

गौरतलब है कि मिशन रेबीज़ की स्थापना वर्ष 2013 में ब्रिटेन के वेटरिनेरियन डॉ. ल्यूक गैम्बल ने वर्ल्डवाइड वेटरिनरी सर्विस (ङ्खङ्कस्) के प्रमुख प्रोजेक्ट के रूप में की थी। यह संगठन विश्वभर में कुत्तों के सामूहिक टीकाकरण, बीमारी की निगरानी और जनजागरूकता कार्यक्रमों के जरिए रेबीज़ को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

इसी क्रम में लहित टीम उत्तरकाशी ने भी इस मुहिम को जनआंदोलन का रूप देने की ठानी है। टीम पिछले वर्ष रेड क्रॉस उत्तरकाशी और पशुपालन विभाग के सहयोग से 500 से अधिक कुत्तों का एंटी रेबीज़ टीकाकरण करा चुकी है। यही नहीं, इस अभियान का विस्तार देहरादून के कुछ क्षेत्रों तक भी किया गया था।

इस वर्ष की वैक्सीनेशन ड्राइव में गौरव सिंह परमार, रोनक चंद रमोला, खुशी, आशुतोष नौटियाल, आशुतोष रावत, राहुल नेगी, केशव, जितेन्द्र, सलोनी, अजीत, आरती, विश्वास डोभाल, सन्यम, विशाल कलूरा, शशांक नौटियाल, सौरभ और अनुज जैसे युवाओं ने पूरी सक्रियता और समर्पण के साथ भाग लिया।

लहित टीम न केवल वैक्सीनेशन और रेस्क्यू कार्यों में जुटी है, बल्कि समय-समय पर फूड ड्राइव्स, रिफ्लेक्टिव कॉलर अभियान, वॉटर फीडर प्रोग्राम और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करती रही है। वन विभाग की मदद से टीम ने अब तक कई वन्यजीव रेस्क्यू ऑपरेशनों को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिनमें हिरण, भारतीय जल शाग, उल्लू और शिकारी पक्षियों का बचाव शामिल है।

बिना स्थायी शेल्टर और सीमित संसाधनों के बावजूद, टीम ने ऑन-स्पॉट ट्रीटमेंट और रेस्क्यू कार्यों से कई पशुओं को नई जिंदगी दी है। इस दौरान टीम को एस.डी.एम. भटवाड़ी सुश्री शालिनी नेगी का भी निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा है। पशु कल्याण के प्रति उनका संवेदनशील रवैया टीम के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहा है।

लहित एनिमल वेलफेयर टीम का विजन है कि स्थानीय फीडर्स, युवाओं और ग्रामीणों को साथ लेकर एक स्वस्थ और सुरक्षित समुदाय तैयार किया जाए, जहाँ इंसान और पशु दोनों भयमुक्त होकर जीवन जी सकें।

यह मुहिम न केवल उत्तरकाशी को रेबीज़-फ्री ज़ोन बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि पूरे प्रदेश में पशु कल्याण की नई सोच को भी जन्म देती है।

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की कार्यशाला में स्वदेशी को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प

पथ प्रवाह, संवाददाता,

उत्तरकाशी। भाजपा जिला कार्यालय ज्ञानसू में शनिवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की कार्यशाला का आयोजन जिला अध्यक्ष नागेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में आत्मनिर्भर भारत उत्तराखंड प्रदेश सहसंयोजक विशाल गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. स्वराज विद्वान, जिला प्रभारी नवीन ठाकुर, आत्मनिर्भर भारत जिला संयोजक महावीर सिंह नेगी और पूर्व विधायक केदार सिंह रावत समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

मुख्य वक्ता विशाल गुप्ता ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि ÷हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी÷ की भावना के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, जीएसटी सुधार, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और स्स्स्ध प्रोत्साहन जैसे कदम ऐतिहासिक हैं, जिनसे देश की आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी। जिला प्रभारी नवीन ठाकुर ने कहा कि इस अभियान का मूल उद्देश्य हर भारतीय को जोड़ना और प्रेरित करना है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के अधिकतम प्रयोग का आह्वान करते हुए कहा कि यह पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनभागीदारी से निर्मित राष्ट्रीय शक्ति है। जिला अध्यक्ष नागेंद्र चौहान ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे घर-घर जाकर स्वदेशी उत्पादों का प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का विस्तार है, जिसका लक्ष्य भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस अवसर पर पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, डॉ. स्वराज विद्वान, किशोर भट्ट, हरीश डंगवाल, जिला महामंत्री महावीर नेगी, परशुराम जगूड़ी, राजेन्द्र सिंह गंगाडी, मनोजेन्द्र सिंह रावत, प्रेमदत्त भट्ट, राजीव नौटियाल, आलेंद्र भंडारी, परवीन असवाल, अमित रावत, अनीता परमार, राजीव परमार, रजनीश चौहान, कुलदीप नेगी, भारत सिंह बिष्ट, रमेश सेमवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

शिव नगरी उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने की उठी मांग, संतों-समाजसेवियों और युवाओं ने लिया संकल्प

पथ प्रवाह, संवाददाता, उत्तरकाशी।

हिमालय की गोद में बसी पवित्र नगरी उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने की मांग को लेकर आज शनिवार को नगर के हनुमान मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले विभिन्न धार्मिक संगठनों, समाजसेवियों और युवाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर व जनपद भर से आए साधु-संतों, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, प्रजापति समाज, ब्रह्माकुमारी संस्था, गायत्री परिवार, संस्कृत महाविद्यालय के छात्र तथा विभिन्न गांवों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने की दिशा में आगे की रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर अरविंद कुडियाल ने पंचकोसी क्षेत्र को धार्मिक नगरी घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि उत्तरकाशी अपने प्राचीन धार्मिक महत्व और काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे देवालयों के कारण विशेष पहचान रखती है। इसे धार्मिक नगरी का दर्जा देकर इसके गौरव को पुनर्स्थापित किया जाए। लंबगांव टिहरी से आए समाजसेवी देवी सिंह पंवार ने कहा कि शिव नगरी उत्तरकाशी वास्तव में काशी विश्वनाथ की नगरी है, जिसका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। राज्य सरकार को इसे धार्मिक नगरी घोषित कर विशेष पैकेज जारी करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए हम अनशन और भूख हड़ताल तक करने को बाध्य होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक नगरी का स्वरूप तभी सार्थक होगा जब सबसे पहले यहां मांस व शराब पर रोक लगे और आमजन स्वयं अपने घरों से इनका परित्याग करें। वरिष्ठ समाजसेवी दिनेश पंवार ने कहा कि उत्तरकाशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक चेतना, आस्था और सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे अगली पीढ़ियों तक जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। बैठक में उपस्थित विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष अजय प्रकाश बडोला, जिला मंत्री कीर्ति सिंह महर, नगर संयोजक सुशील शर्मा, उमेद सिंह चौहान, महिपाल पंवार, मुनेन्द्र रावत, कुलबीर सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में युवा प्रतिनिधियों ने उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने और इसे पुनः ÷धर्म और संस्कृति की धरती÷ के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया। व्यापार मंडल से अध्यक्ष उत्तम सिंह गोसाई, शंकर सिंह गोसाई, प्रजापति ब्रह्माकुमारी से प्रतिनिधि गोपाल दत्त जोशी, सूरज रामलाल नेगी, देवी सिंह पोखरियाल, पंडित शिव प्रसाद भट्ट, विद्याधर नौटियाल, राज्य आंदोलनकारी डॉ. विजेंद्र सिंह पोखरियाल, पंडित भीमदेव थपलियाल, रामकृष्ण शास्त्री, धर्मेंद्र पंवार, अनुराग शिवनारायण भट्ट समेत अनेक समाजसेवियों और छात्रों ने इस अभियान में सक्रिय सहयोग का संकल्प व्यक्त किया।

एक नजर

उत्तराखंड में एक नौवीं कक्षा की छात्रा ने बच्ची को दिया जन्म, आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद से बेहद चौंकाने वाले खबर सामने आई है। महज 14 साल 10 महीने की नाबालिग किशोरी ने शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। यह घटना सामने आते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पीड़िता एक स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा है। शुक्रवार तड़के करीब पांच बजे किशोरी को उसकी माँ अस्पताल लेकर पहुँची, जहां जांच में उसके गर्भवती होने का पता चला। अस्पताल प्रशासन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसी बीच, किशोरी ने सामान्य प्रसव से बच्ची को जन्म दिया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी युवक का नाम सूरज है, जो अल्मोड़ा जिले के शीतलाखेत का रहने वाला है और नैनीताल में एक रेस्टोरेंट में काम करता है। करीब दो साल पहले उसकी पहचान फेसबुक के जरिए किशोरी से हुई थी। धीरे-धीरे संपर्क बढ़ा और आरोपी ने उसका यौन शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि किशोरी के बच्ची को जन्म देने की सूचना मिलते ही आरोपी सूरज भी अस्पताल पहुँच गया और वहाँ मौजूद लोगों को मिठाई बाँटने लगा। अस्पताल की सूचना पर कोतवाल हेम पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) ऐक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है।

चमोली के सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय की मिली मंजूरी, सीएम पुष्कर धामी ने पीएम और केंद्रीय मंत्रियों को जताया आभार

पथ प्रवाह, चमोली। जनपद चमोली के सवाड़ गांव में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति मिलने के बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और केंद्रीय मंत्रीमंडल का विशेष आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि सवाड़ गांव में क्षेत्रीय जनता की लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय की मांग रही है, जिसके लिए उन्होंने निरंतर केंद्रीय स्तर पर अनुरोध किया। इसके परिणामस्वरूप अब इस सीमांत क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा, जिससे स्थानीय छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और क्षेत्र को नई पहचान भी मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल और समृद्ध शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। शिक्षकों को नवीनतम प्रशिक्षण और शिक्षण नवाचारों से जोड़कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ-साथ उत्तम अध्ययन माहौल भी उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आश्वस्त किया कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि यह क्षेत्र के सामाजिक और शैक्षिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आर्थिक तंगी से स्कूल छोड़ चुकी दो बालिकाओं का कराया दाखिला

पथ प्रवाह संवाददाता। पिथौरागढ़। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस की एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (।॥ज्ञ) द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं जागरूकता कार्यक्रम के दौरान यह संज्ञान में आया कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में रह रही दो बालिकाएं, जिनके माता-पिता मूलतः बरेली निवासी हैं तथा पेंटर का कार्य करते हैं, पिछले लगभग 8-9 वर्ष पूर्व झारखंड चले गए थे। वहां पर बालिकाओं का दाखिला कराया गया था। वर्तमान में परिवार पिछले 2 माह से पिथौरागढ़ में रह रहा है, किन्तु आर्थिक तंगी के कारण बालिकाओं को पुनः स्कूल नहीं भेज पा रहा था। एएचटीयू टीम द्वारा बालिकाओं एवं उनके परिजनों की काउंसलिंग की गई तथा उन्हें शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक कर विद्यालय में पुनः दाखिला कराने हेतु प्रेरित किया गया। टीम एवं राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल, मंडप के शिक्षकों के सहयोग से दोनों बालिकाओं का विद्यालय में दाखिला कराया गया। दोनों को कॉपी, किताबें, स्कूल ड्रेस एवं अन्य आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई गई।

एक नजर

देव भूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी विकसित हो रहा उत्तराखंड- महेश नेगी

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। उत्तराखंड देवभूमि के साथ-साथ खेल भूमि भी बनती जा रही है। यह बात उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए है। उत्तराखंड के कई शहरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा चुका है। महेश नेगी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से अब उत्तराखंड में इंटरनेशनल स्तर के 25 खेल एक साथ खेले जा सकते हैं। इन खेलों में शूटिंग, साइकलिंग, फेंसिंग, जल क्रीड़ा और हॉकी जैसे मुख्य खेल शमिल हैं। बताया कि हरिद्वार में हुए राष्ट्रीय खेलों के बाद हल्द्वानी में इंटरनेशनल फेंसिंग प्रतियोगिता अभी हाल ही में समाप्त हुई है। जिसमें 17 देशों ने भाग लिया था। देहरादून में बास्केटबॉल जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। कहा कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल में कीर्तिमान स्थापित किये हैं। राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को गोल्ड सिल्वर और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है। खिलाड़ियों को नौकरी देने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में बास्केटबॉल के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास तिवारी, सचिव संजय चौहान, जिला अध्यक्ष ललित नैयर, ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भगवान कार्की, बास्केटबॉल के अध्यक्ष बजाज हीरा सिंह आदि मौजूद रहे।

शोरूम मालिक की हत्या में शामिल अन्नपूर्णा भारती पुरी अखाड़े से निष्कासित

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। अलीगढ़ में विगत 26 सितंबर को शोरूम स्वामी की हत्या में संलिप्त श्री पंचायती अखाड़ा तपोनिधि निरंजनी की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पुरी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है।अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने बताया कि अन्नपूर्णा भारती पुरी को ना तो उन्होंने कभी दीक्षा दी और ना ही वह उनकी शिष्य है। उनके कृत अक्षम्य में है। इस कारण से अखाड़े द्वारा उनको निष्कासित कर दिया गया है। बतादें अलीगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बाइक शोरूम चलाने वाले 25 वर्षीय अभिषेक गुप्ता की बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय और उनके पति अशोक पांडेय का नाम सामने आया। अभिषेक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए शूटर मोहम्मद फजल के हवाले से घटना का खुलासा किया था। शूटर ने पुलिस को बताया था कि सौदा डेढ़ महीने पहले तय हुआ था। इसके लिए उन्हें एक लाख रुपये एडवांस मिले थे। गोली उसके साथी आसिफ ने चलाई थी। दरअसल, अभिषेक गुप्ता हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा के रहने वाले थे। और हाल ही में खैर कस्बे में उन्होंने टीवीएस बाइक का शोरूम खोला था। 26 सितंबर की रात पिता और चचेरे भाई के साथ शोरूम बंद कर घर लौटते समय खेरेश्वर मंदिर चौराहे पर बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। जैसे ही वे बस में चढ़ने लगे। पीछे से गोली मार दी गई। और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने की आकांक्षी कार्यक्रमों की समीक्षा

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने आकांक्षी जनपद कार्यक्रम एवं आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य एवं पोषण विभाग के संकेतकों की प्रगति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में सीडीओ ने गर्भवती महिलाओं के एएनसी चेकअप, होम डिलीवरी, लिंगानुपात, गंभीर एनीमिया, एसएएम एवं एमएएम जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों में सुधार लाने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के संकेतकों में अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल इसमें सुधार सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, कृषि, आधारभूत अवसंरचना, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास से संबंधित संकेतकों की भी विभागवार समीक्षा की गई। सीडीओ ने आकांक्षी जनपद कार्यक्रम से संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने संकेतकों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट आगामी सोमवार तक अनिवार्य रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निरंतर की जा रही है कार्यवाही

जिलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिये हैं कि जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण है उन्हें तत्काल कार्रवाई करते हुए हटाया जाए।

उप जिलाधिकारी हरिद्वार जितेन्द्र कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में सिंचाई विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वधान में तहसील हरिद्वार के अंतर्गत दूधिया बन्ध में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। उन्होंने बताया कि दूधिया बन्ध में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाने के लिए अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नोटिस दिए गए थे लेकिन उनके द्वारा स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिस पर प्रशासन ने अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाए। अभियान के दौरान लगभग 100 अतिक्रमण हटाए गए, शेष बचे हुए अतिक्रमण भी शीघ्र हटाए जाएँगे। अतिक्रमण हटाने के दौरान चलाए गए अभियान के दौरान उपजिलाधिकारी, पुलिस एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

धर्म छिपाकर नाबालिग को लेकर हुआ फरार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पथ प्रवाह संवाददाता। धर्म छिपाकर और अपना नाम बदलकर नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने करीब 400 सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

पुलिस के मुताबिक 29 सितम्बर को एक महिला ने कोतवाली नगर हरिद्वार में आकर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उसने बताया कि उसकी पुत्री का घर से रोजाना की तरह शुलभ शौचालय ऋषिकुल गयी थी जो वापस नहीं आयी है। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। लड़की की बरामदगी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल से लेकर आस-पास व सम्भावित स्थानों पर लगे लगभग 400 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया और मुखबिर तन्त्र को अलर्ट किया। इसी दौरान लापता नाबालिग उसी रात रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से जाती दिखायी दी। जिस पर संबंधित जीआरपी, आरपीएफ से संपर्क करते हुए गुमशुदा के फोटो प्रसारित करते हुए तलाश की गई। पुलिस को उस वक्त सफलता मिली जब शनिवार को उसे नारसन गुरुकुल से सकुशल बरामद किया गया। पुलिस ने उसका अपहरण करने वाले आरोपी सहमत उर्फ अंकित पुत्र महबूब निवासी छोटी नारसन गुरुकुल थाना मंगलौर जिला हरिद्वार को मौके से ही गिरफ्तार किया। लड़की को आवश्यक कार्यवाही के बाद सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया।

ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन- अलीपुर में लगी पुलिस की चौपाल

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार। मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के लिए ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत नशा मुक्त शहर, नशा मुक्त गांव एवं ज़िंदगी को हां, नशे को ना अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से ग्राम अलीपुर में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों के साथ नशे की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा की गई। उन्हें बताया गया कि नशे के कारोबार को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति नशे के कारोबारियों की सहायता करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीणों को नशा करने वाले व्यक्तियों की काउंसलिंग कर उन्हें नशा मुक्त करने तथा नशा बेचने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में नशा मुक्त शहर-नशा मुक्त गांव अभियान के अन्तर्गत ÷ज़िंदगी को है, नशे को ना÷ की शपथ दिलाई गई। इसके अतिरिक्त, उपस्थित लोगों को साइबर सुरक्षा एवं यातायात सुरक्षा के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में नशा मुक्त वाहिनी टीम सहित थाना बहादराबाद पुलिस एवं स्थानीय ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता रही।

थाना पथरी पुलिस ने इब्राहिमपुर में लगायी चौपाल

हरिद्वार। थाना पथरी पुलिस ने ग्राम इब्राहिमपुर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को नशे के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों को अवैध मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों, साइबर अपराधों, तथा कालनेमी अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।

ग्रामवासियों एवं नवयुवकों को जागरूक करते हुए बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति नशे के कारोबारियों की मदद करता हुआ पाया गया, तो उसके विरुद्ध भी विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। चौपाल में उपस्थित सभी व्यक्तियों को यह भी अवगत कराया गया कि नशा बेचने या करने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समाज को नशा मुक्त बनाया जा सके। इसके साथ ही साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय भी विस्तार से बताए गए। ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया। ग्रामवासियों द्वारा चौपाल के दौरान विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए गए और पुलिस को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया, जिससे क्षेत्र में व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

एक नजर

महिला आयोग की सदस्य ने की पूछताछ, प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने उठाए कार्रवाई पर सवाल

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार। जिला महिला अस्पताल में गर्भवती महिला के फर्श पर बच्ची को जन्म देने के आरोपों की जांच करने के लिए महिला आयोग की सदस्य कमला जोशी हरिद्वार पहुंची। शनिवार को उन्होंने अस्पताल की महिला डॉक्टर स्टाफ नर्स, आशा कार्यकर्ता और महिला के पति से बंद कमरे में पूछताछ की।

पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि डिलीवरी कराने में लापरवाही और गलत व्यवहार जरूर हुआ है लेकिन बच्ची फर्श पर पैदा होने के आरोप निराधार निकले है। जिला महिला अस्पताल में ब्रह्मपुरी निवासी गर्भवती महिला बीते रविवार को रात साढ़े नौ बजे आयी थी। उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि महिला चिकित्सक की लापरवाही और अमानवीय व्यवहार के चलते महिला को समय से लेबर रूम में नहीं ले जाया गया। आरोप लगाया था कि गर्भवती महिला को समय से लेबर रूम में नहीं ले जाने से फर्श पर ही उसकी बच्ची पैदा हुई थी।

वहीं दूसरी ओर प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने शनिवार को जिला महिला अस्पताल के सभागार में प्रेस वार्ता कर अस्पताल में गर्भवती महिला से अभद्रता के मामले में सीएमओ की ओर से बिना जांच किए कार्यवाही को एकतरफा बताया है। कहा कि इससे डॉक्टरों का मनोबल गिरेगा। साथ ही कार्यक्षमता में भी गिरावट आएगी। संघ के प्रदेश महासचिव डॉ. राजेश कुंवर ने कहा कि सीएमओ के इस फैसले से डॉक्टरों में भारी आक्रोश है। इस मामले में मेला अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेश गुप्ता का कहना है कि इस प्रकार की वीडियो वायरल कर सरकारी अस्पताल की छवि खराब करने की कोशिश की गई है।

प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने की बैठक

पथ प्रवाह संवाददाता। पिथौरागढ़। प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी गोस्वामी ने देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रशिक्षु अधिकारियों से उनके जनपद पिथौरागढ़ भ्रमण के अनुभवों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से जनपद में किए गए भ्रमण, प्रशासनिक कार्यों की समझ, विकास कार्यों की समीक्षा तथा क्षेत्रीय चुनौतियों के संदर्भ में संवाद स्थापित किया। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बताया कि पिथौरागढ़ जनपद भौगोलिक दृष्टि से अति संवेदनशील है तथा सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां प्रशासनिक दक्षता व तत्परता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आपदा प्रबंधन तथा जन सहभागिता से जुड़े विषयों पर भी अवगत कराया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए जनपद में मिले सहयोग व क्षेत्र की विविधताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ भ्रमण से उन्हें जमीनी स्तर पर कार्य करने की गहन समझ मिली है, जो उनके प्रशासनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी गण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

महिला से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह संवाददाता। पिथौरागढ़। महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को जाजरदेवल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नेपाल निवासी एक महिला द्वारा थाना जाजरदेवल में तहरीर दी गई कि जब वह अपनी बहन के घर पिथौरागढ़ से दारचुला लौट रही थी, तो वह रास्ता भटक गई और लिफ्ट मांगते हुए लछैर वाली रोड पर पहुँच गई। लछैर में सुनसान सड़क पर एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़-छाड़ की और महिला के विरोध करने पर उसे धमकाकर उसके पैसे छीनकर पहाड़ से फेंक दिया। तहरीर के आधार पर थाना जाजरदेवल में अभियोग पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष मनोज पाण्डे के नेतृत्व में टीम ने अभियुक्त की तलाश शुरू की। सुरागरसी और पतारसी के बाद अभियुक्त कमलेश जोशी, पुत्र हरीदत्त जोशी, निवासी लछैर, थाना जाजरदेवल, उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के खिलाफ 2023 में लछैर गाँव से पेयजल की सामग्री चोरी करने का भी अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त को न्यायिक कार्यवाही के बाद न्यायालय में पेश किया गया।

आर्थिक तंगी से स्कूल छोड़ चुकी दो बालिकाओं का कराया दाखिला

पथ प्रवाह संवाददाता। पिथौरागढ़। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस की एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (।ऌ) द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं जागरूकता कार्यक्रम के दौरान यह संज्ञान में आया कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में रह रही दो बालिकाएं, जिनके माता-पिता मूलतः बरेली निवासी हैं तथा पेंटर का कार्य करते हैं, पिछले लगभग 8-9 वर्ष पूर्व झारखंड चले गए थे। वहां पर बालिकाओं का दाखिला कराया गया था। वर्तमान में परिवार पिछले 2 माह से पिथौरागढ़ में रह रहा है, किन्तु आर्थिक तंगी के कारण बालिकाओं को पुनः स्कूल नहीं भेज पा रहा था। एएचटीयू टीम द्वारा बालिकाओं एवं उनके परिजनों की काउंसलिंग की गई तथा उन्हें शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक कर विद्यालय में पुनः दाखिला कराने हेतु प्रेरित किया गया।

वडडा की ऐतिहासिक रामलीला का पूर्व सैनिकों ने किया उद्घाटन

पथ प्रवाह संवाददाता।

पिथौरागढ़। सौर घाटी की दशकों पुरानी रामलीला की परंपरा का निर्वहन आज भी भव्य रूप से वडडा क्षेत्र पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस बार इस रामलीला का उद्घाटन जनपद के इतिहास में पहली बार पूर्व सैनिकों द्वारा किया गया जो की ऐतिहासिक रामलीला पर मिसाल बना। सैकड़ो लोग इसके साक्षी रहे।

शुक्रवार एकादशी के दिन जब देश के पूर्व सैनिकों द्वारा रामलीला मंचन का दीप जला, फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया रामलीला कमेटी द्वारा इसे देश को समर्पित तथा सेना के गर्व से परिपूर्ण उद्घाटन बताया, जो कि सीमांत जनपद के सीमा से लगाते हुए क्षेत्र से अपने देश और सेना के शौर्य को समर्पित करते हुए कहा गया। कल इस उद्घाटन समारोह पर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक तथा असम राइफल्स के सैनिक मौजूद रहे सभी के द्वारा रामलीला कमेटी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे गौरवान्वित उद्घाटन कहा गया सैनिकों ने इस उद्घाटन को अमर बलिदानियों तथा सेना के ऑपरेशन सिंदूर को जांबाज सैनिकों को समर्पित किया गया। पूर्व सैनिक संगठन का जिला पंचायत सदस्य कपिल भंडारी द्वारा स्वागत किया गया। वहीं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष कुंडल गिरी तथा उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्वारा पूर्व सैनिक संगठन को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।

कल रामलीला की शुरुआत गणेश पूजा, कलश यात्रा तथा मां कामाख्या नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय के बच्चों द्वारा रुद्री पाठ के साथ, विधिवत उद्घाटन के पश्चात प्रथम दिन की रामलीला में रावण को अपने बल के वशीभूत होकर भगवान शिव से असुरों का प्रतिनिधित्व करने का श्राप प्राप्त होने से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता के जन्म की लीला का कलाकारों द्वारा जीवंत मंचन किया गया।

रामलीला उद्घाटन कार्यक्रम पर ग्राम प्रधान सुवाकोट प्रकाश सोन,आसाम राइफल के सचिव हेमंत सोन,संगठन के कैप्टेन दिवान सिंह सेना मैडल, भूपेंद्र सिंह बोहरा, उमेश फुलेरा, श्याम विश्वकर्मा, ओम प्रकाश, नवीन गुरुरानी सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक तथा आम जन मानस शामिल रहे।

प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने की बैठक

पथ प्रवाह संवाददाता। पिथौरागढ़। प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी गोस्वामी ने देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रशिक्षु अधिकारियों से उनके जनपद पिथौरागढ़ भ्रमण के अनुभवों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से जनपद में किए गए भ्रमण, प्रशासनिक कार्यों की समझ, विकास कार्यों की समीक्षा तथा क्षेत्रीय चुनौतियों के संदर्भ में संवाद स्थापित किया। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बताया कि पिथौरागढ़ जनपद भौगोलिक दृष्टि से अति संवेदनशील है तथा सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां प्रशासनिक दक्षता व तत्परता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आपदा प्रबंधन तथा जन सहभागिता से जुड़े विषयों पर भी अवगत कराया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए जनपद में मिले सहयोग व क्षेत्र की विविधताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ भ्रमण से उन्हें जमीनी स्तर पर कार्य करने की गहन समझ मिली है, जो उनके प्रशासनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी गण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

आपदा राहत व बचाव कार्यों में सराहनीय योगदान देने वाले पुलिस व सुरक्षा बलों के अधिकारी-कर्मचारी सम्मानित

पथ प्रवाह, ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

प्रदेश में विभिन्न आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के अधिकारी एवं कर्मियों को आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया।

यह कार्यक्रम अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जांबाजों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदाओं के समय राहत और बचाव में इन बलों का कार्य अद्वितीय है। उन्होंने विशेष रूप से उत्तरकाशी जिले के हर्षिल-धराली क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले उत्तरकाशी पुलिस के अपर उपनिरीक्षक प्रमोद उनियाल और आरक्षी नरेश का उल्लेख करते हुए उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनका साहस और त्वरित कार्रवाई अनेक जिंदगियां बचाने में सहायक बनी।

कार्यक्रम में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के विभिन्न जवानों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मौके पर अर्पित फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि आपदा के समय अग्रिम पंक्ति में कार्य करने वाले इन कर्मियों का मनोबल बढ़ाना समाज की जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों से भविष्य में और अधिक सशक्त समन्वय की अपेक्षा जताई, ताकि प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपदा आने पर त्वरित और प्रभावी बचाव कार्य किए जा सकें।

जिला स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का 5 अक्टूबर को शुभारंभ

पथ प्रवाह, संवाददाता

जिला हरिद्वार मुक्केबाजी संघ के तत्वावधान में जिला स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 5 अक्टूबर 2025 (रविवार) को योगस्थली परिसर, रोशनाबाद स्टेडियम, हरिद्वार में किया जाएगा। यह प्रतियोगिता जिले के उभरते मुक्केबाजों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का आयोजन दोपहर 12ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक होगा। इस अवसर पर जिले भर के खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। जिला मुक्केबाजी संघ के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों एवं खिलाड़ियों की ओर से समाज के सम्मानित नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं खेलप्रेमियों से करबद्ध अनुरोध किया गया है कि वे अपने अमूल्य समय से कुछ क्षण निकालकर खिलाड़ियों को आशीर्वाद प्रदान करें तथा अपनी गरिमामयी उपस्थिति से प्रतियोगिता का उत्साहवर्धन करें।

संघ के उपाध्यक्ष रोहन सहगल ने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण को देखकर हरिद्वार मुक्केबाजी के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। उन्होंने कहा कि ÷माननीय अतिथियों की उपस्थिति युवा मुक्केबाजों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 41, शांतिपुरम, जगजीपुर, कनखल, हरिद्वार पिन-249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, सुरेन्द्र पाल सिंह (ब्यूरो चीफ, उत्तरकाशी) 7376757899 वेबसाई- www.pathpravah.com